

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(सं0 पटना 367)

8 श्रावण 1934 (शO) पटना, सोमवार, 30 जुलाई 2012

गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

30 जुलाई 2012

सं0 स्था०-03-07/2005-1470—वित्त विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या 4685, दिनांक 25.06.2003 तथा 1802, दिनांक 23.03.2006 एवं स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में गन्ना उद्योग विभाग के ईख सम्वर्ग के निम्निलिखित पदाधिकारी को 12 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर उनके नाम के सामने अंकित तिथि से वेतनमान् 9300-34500 रु०+ग्रेड पे 5400 रु० में प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र॰ सं॰	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के लाभ की स्वीकृति की
7/0 (10	141141717 47 11 74 14 11 1	तिथि
		18(1)=1
01.	श्री उमेश सिंह,	28.09.2007
	ईख पदाधिकारी,	
	रामनगर अंचल, बेतिया	
02.	श्री जय प्रकाश नारायण सिंह,	28.09.2007
	ईख पदाधिकारी, गोपालगंज	
03	श्री कुमार अविनाश चन्द्र,	10.10.2007
	ईख पदाधिकारी, पूर्णिया	

- 2. प्रथम उन्नयन का लाभ प्राप्त करने के बाद पदधारक की पदीय स्थिति में कोई परिवर्त्तन नहीं होगा।
- 3. इस योजना के अधीन यह वित्तीय उन्नयन विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत लाभ होगा। अतः सम्वर्ग में कनीय पदाधिकारियों के सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजनान्तर्गत उच्चतर वेतनमान प्राप्त होने के आधार पर वरीय पदाधिकारी को अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन / वेतन संरक्षण देय नहीं होगा।
- 4. भविष्य में सम्बद्ध पदाधिकारी / कर्मी के सम्वर्ग से संबंधित वित्त विभाग, बिहार, पटना अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके वेतनमान से संबंधित यदि कोई निर्णय लिये जाते है तो यह वित्तीय उन्नयन तद्नुसार प्रभावित होते हुए रूपभेदित किया जा सकेगा।
- 5. वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या 1802, दिनांक 23.03.2006 में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन का निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम 22 (I) में निहित प्रावधान के अनुसार निर्धारण किया जायेगा।
- 6. उपर्युक्त पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने अथवा यदि वित्त विभाग / सक्षम प्राधिकार के द्वारा इस वित्तीय उन्नयन के संबंध में किसी प्रकार की आपित उठायी जायेगी या मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा इस संबंध में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेश नियमानुसार अवक्रमित / संशोधित कर दिया जायेगा तथा भुगतान की गई राशि की वसूली / प्रतिपूर्त्त कर ली जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अनिल कुमार झा, सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 367-571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in